C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XVIII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No.15, Tuesday, August 23, 2011/Bhadra 1, 1933(Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.281 to 300	8-93
Unstarred Question Nos.3221 to 3450	94-634

PAPERS LAID ON THE TABLE **635-640**

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 3018 DATED 15.3.2011 REGARDING INNOVATIVE COURSE FOR YOUTH ALONGWITH REASONS FOR DELAY **641**
Shri Ajay Maken

MATTERS UNDER RULE 377 **642-656**

(i) Need to expedite approval for four laning of stretch of N.H. 17 between Poladpur and Patradevi in Maharashtra

Dr. Nilesh Narayan Rane 642

(ii) Need to provide option of learning in mother tongue/regional language to students in Kendriya Vidyalayas

Shri Narayan Singh Amlabe 643

(iii) Need to provide houses to poor and homeless people belonging to General Category under Indira Awas Yojana

Rajkumari Ratna Singh 644

(iv) Need to provide financial assistance to the Boat Racing Associations in Kerala

Shri Kodikunnil Suresh 645

(v) Need to provide relief to the people affected due to flood in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Dr. Vinay Kumar Pandey 646

(vi) Need to allocate coal to thermal power units in Gujarat from Western Coal Fields

Shri Harin Pathak 647

(vii) Need to prohibit the practice of carrying night soil in the country

Shri Anurag Singh Thakur 648

(viii) Need to provide ownership of land and caste certificates to migrated Bengali and Sindhi people living in Khajuraho Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Jeetendra Singh Bundela 649

(ix) Need to provide Scheduled Tribe certificates to all the persons belonging to the 'Gond' Tribe in Uttar Pradesh

Shri Bal Kumar Patel 650

(x) Need to develop the site of Mausoleum of Madarshah in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh as a tourist place of national importance

Shri Ashok Kumar Rawat 651

(xi) Need to provide immediate financial assistance to the patients seeking help from Prime Minister's National Relief Fund

Shri Maheshwar Hazari 652

(xii) Need to extend agricultural loan to farmers and provide adequate quantity of subsidized fertilizers to them in Tamil Nadu.

Shri D. Venugopal 653

(xiii) Need to construct a Road Over Bridge at Nadakkavu in Palakkad, Kerala

Shri M.B. Rajesh 654

(xiv) Need to create a new railway division under East Coast Railway Zone in Odisha

Shri Mohan Jena 655

(xv) Need to reopen the Andhra Cement Company in Guntur District in Andhra Pradesh

Shri M. Venugopala Reddy 656

OBSERVATION BY THE SPEAKER **662-663**
Notices Under Rule 193 for discussion on issue of corruption

COMMITTEE ON AGRICULTURE **664**
21st Report

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 666

Member-wise Index to Unstarred Questions 667-672

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 673

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 674-675

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 23, 2011/Bhadra 1, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नम्बर 281, डॉक्टर रत्ना डे।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद की कमी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम आपको 12 बजे मौका देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग ऐसा नहीं करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रामकिशुन जी शून्य प्रहर में आप का विषय ले लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रामकिशुन जी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस आया है। हम आपका विषय जीरो आवर में ले लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि क्वेश्चन आवर को चलाने की जगह, भ्रष्टाचार पर बहस आज ही शुरु करनी चाहिए। ...(व्यवधान) यदि यह कर दें...(व्यवधान)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam, we have given notice for Adjournment Motion. … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): We have given the notice for the suspension of Question Hour. Please listen to us. Please listen to all the leaders.… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : संपूर्ण विपक्ष की तरफ से विनती है ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right. Let me just tell you that there is no rule for the Members to ask the suspension of Question Hour. However, as a special case, as I have done last time, I will give some time to hon. Members to speak. But, after that, let me run the Question Hour.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उसके बाद हाउस रन करने दीजिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब आप अपनी बात बोल लेंगे तब हाउस रन करने में क्या हर्ज है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हाँ, आप को भी बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जिनका नोटिस है हम उनको बुलवा लेते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद, अध्यक्ष जी, हम तीन दिन के अंतराल के बाद आज सदन में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इन तीन दिनों में देश के अलग-अलग स्थानों पर जो कुछ देखने को मिला, वह चिंता पैदा करता है।

अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार के कारण गुस्साए हुए लोग सड़कों पर उतरे और लाखों की संख्या में उतरे। संतोष की बात केवल एक है कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहा। लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर अपनी बात कहते थे। लोग भारत माता की जय बोल कर अपनी बात कहते थे। लोग वंदेमातरम का उद्घोष करके अपनी बात कहते थे। लेकिन सरकार यह कह कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हम क्या करें यह तो

आंदोलनकारी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जड़ में सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार के छोटे-मोटे कांड तो आमतौर पर उजागर होते रहते थे लेकिन पिछले एक वर्ष में जितने बड़े व्यापक स्तर पर, जितने बड़े पैमान पर, जितनी बड़ी राशि के भ्रष्टाचार के कांड उजागर हुए और एक के बाद एक उजागर होते चले गए यह उसका परिणाम है कि आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आदर्श सोसायटी थमा नहीं कि टू-जी आ गया, टू-जी थमा नहीं कि सीडब्ल्यूजी आ गया, सीडब्ल्यूजी थमा नहीं कि एयर इंडिया आ गया, एयर इंडिया थमा नहीं कि केजी बेसिन आ गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, लोग यह कहते हैं कि एक तरफ करोड़ों का धन विदेशी बैंकों में जमा है और दूसरी तरफ गली की नाली और गांव का खड़ंजा बनवाने के लिए हम आवेदन देते-देते थक जाते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि पैसा उपलब्ध नहीं है, राशि उपलब्ध नहीं है। हमें देखना होगा कि आखिर यह गुस्सा किस पर है और इस भ्रष्टाचार के बाद इस आग में घी डालने का काम उस सरकारी लोकपाल बिल के ड्राफ्ट ने किया है जो लचर और पिलपिला है। एक ऐसा बिल जिसके न दांत हैं न आंत है।...(व्यवधान) एक ऐसा बिल इस सरकार ने पेश किया है।

आपको याद होगा कि इसके इंट्रोडक्शन के समय भी मैंने खड़े होकर कहा था कि यह एकदम निष्प्रभावी बिल है। वह बिल जिसके दायरे में प्रधान मंत्री नहीं हैं, वह बिल जो सरकारी बाहुल्य कमेटी से लोकपाल को चुनता है, जो बिल सरकार द्वारा लोकपाल को हटाने का प्रावधान करता है। सरकारी बाहुल्य जिस कमेटी में होता है, उसमें विमत को किस तरह दरकिनार किया जाता है, यह मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। केवल वह कमेटी जहां हम तीन मैम्बर्स थे, वहां विमत को दरकिनार करके जिस तरह सीवीसी को अपाइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और मैं उस कमेटी के सदस्य थे।...(व्यवधान) मैं अपनी पूरी तर्कसंगत बात कहती रही।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, आप डिस्कशन करवा दीजिए।...(व्यवधान) इनका नोटिस कुछ और है और बात कुछ और हो रही है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : नोटिस यही है कि पिछले तीन दिनों में क्या हुआ?...(व्यवधान) मेरा नोटिस यही है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, भ्रष्टाचार पर डिस्कशन शुरू करवा दीजिए।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा नोटिस यही है।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Let this be converted into a discussion on corruption under Rule 193…. (*Interruptions*) इन्हें शुरू करने दीजिए।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप मेरा नोटिस पढ़िए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आप नाजायज फायदा उठाती हैं। आप बात कुछ कहती हैं और करती कुछ और हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज अध्यक्षा जी, मेरा नोटिस क्या है?...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस ढंग से नहीं कि सरकार के खिलाफ गलत बात करें।...(व्यवधान) यह बात ऐसी है -- 'न जाने कैसे यह दिल बहलाते हैं, जो खुद नहीं समझे औरों को समझाते हैं।'...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, आप मेरे नोटिस की भाषा संसदीय कार्य मंत्री जी को पढ़वा दीजिए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं सरकार की तरफ से अभी कहता हूं कि सुषमा जी अपनी स्पीच चालू रखें, लेकिन आप इसी को एकदम नियम 193 में कन्वर्ट करके भ्रष्टाचार पर एक रैगुलर डिबेट शुरू करवा दीजिए।...(व्यवधान) यह नहीं कि ये कुछ कह देंगे। एक जगह कहते हैं कि सात जगह इनकी सरकारें हैं। इनकी सरकारों में कहां, क्या हो रहा है, उसका जिक्र नहीं कर रही हैं। यह दिखा रही हैं कि यहां हो रहा है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मेरा नोटिस पहले इन्हें पढ़वा दीजिए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : श्री येदयुरप्पा का क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उनका जिक्र नहीं कर रही हैं।...(व्यवधान) ऐसा नहीं है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मेरे नोटिस का कन्टैंट इन्हें पढ़वा दीजिए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, इन्होंने नोटिस कुछ और दिया था। नोटिस यह दिया था कि जो विकट स्थिति पैदा हुई है...(व्यवधान) हम सोच रहे थे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम नियम 193 के अंतर्गत डिस्कशन शुरू कर लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, यह तो पुरानी फितरत के तहत बात हो रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम 193 के अंतर्गत यह डिस्कशन ले लीजिए। उसमें सब पार्टीज का पार्टीसिपेशन हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, मेरा नोटिस केवल प्रश्न काल स्थगन का है और मेरे नोटिस में यह कन्टैंट है। आप मेरे नोटिस का कन्टैंट उन्हें पढ़कर बता दीजिए। पिछले तीन दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, मैंने केवल उसके ऊपर नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपका नोटिस पढ़ देता हूं -- 'देश में बहुत विकट परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मैं आज प्रश्न काल स्थगित करके इस विषय को उठाना चाहती हूं।' आप बात कुछ और कह रही हैं, नोटिस कुछ और है।...(व्यवधान) बिल्कुल अंतर है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं यही विषय उठाना चाहती हूं।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, हमें ख्याल था कि यह बात कहेंगी कि कैसे इसे सुलझाया जा सकता है।...(व्यवधान) लेकिन यहां सिर्फ वही उंगली उठाई जा रही है और गलत उठाई जा रही है। मैंने जो कहा था, मैं वही फिर दोहरा रहा हूं -- 'न जाने कैसे यह दिल बहलाते हैं, जो खुद नहीं समझे, औरों को समझाते हैं।' यह क्या कर रही हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मेरा प्रश्न काल स्थगन का नोटिस ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मेरा प्रश्न काल का नोटिस, जो परिस्थिति पिछले तीन दिनों में निर्मित हुई है, उस पर है। ...(व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): आप नियम 193 के अन्तर्गत इस पर बहस शुरू कीजिए। ...(व्यवधान) आप रेगुलर डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मेरा नोटिस, पिछले तीन दिनों में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उस पर है। इसलिए मैंने प्रश्न काल स्थगन की बात की। पिछले तीन दिनों में जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस पर मैं बोल रही हूं। हम भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। अगर आपको आज भ्रष्टाचार पर चर्चा शुरू करनी है, तो आज 12 बजे शुरू कर दीजिए। ...(व्यवधान) अगर कल करनी है, तो कल नियम 193 के अन्तर्गत

[*] Not recorded.

भ्रष्टाचार पर चर्चा शुरू कर दीजिए। ...(व्यवधान) हमारी तरफ से डॉ. जोशी भ्रष्टाचार के विषय पर बोलेंगे। ...(व्यवधान) आप यदि यह चर्चा आज 12 बजे शुरू करना चाहते हैं, तो 12 बजे कर लीजिए। ...(व्यवधान) अगर कल करना चाहते हैं, तो कल कर लीजिए। ...(व्यवधान) मेरा प्रश्न काल स्थगन का नोटिस, पिछले तीन दिनों में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उस पर है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमने रूलिंग दे दी है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, the Papers to be laid on the Table of the House. Item No. 2, Kumari Selja.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF CULTURE (KUMARI SELJA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-4952/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Building Development Board, Kavarati, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Building Development Board, Kavarati, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT-4953/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009:-

(i) The Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 318(E) in Gazette of India dated the 13th April, 2011.

(ii) G.S.R.317(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2011, containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 71(E) dated 7th February, 2011.

(iii) The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 202(E) in Gazette of India dated the 9th March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT-4954/15/11)

(2) A copy of the Consumer Protection (Second Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 559(E) in Gazette of India dated the 21st July, 2011 under sub-section (1) of Section 31 of the Consumer Protection Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT-4955/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 1998-1999, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4956/15/11)

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 1999-2000, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4957/15/11)

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 2000-2001, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4958/15/11)

(4) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 2001-2002, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4959/15/11)

(5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 2002-2003, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4960/15/11)

(6) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 2003-2004, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4961/15/11)

(7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 2004-2005, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4962/15/11)

(8) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the year 2005-2006, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT-4963/15/11)

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (1) to (8) above.

(Placed in Library, See No. LT-4963-A/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): On behalf of Shri Namo Narain Meena, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India, Union Government (No.10 of 2011-12)- Scientific Departments- Performance Audit of Role of Tea Board in Tea Development in India, Ministry of Commerce and Industry for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT-4964/15/11)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India, Union Government (No.12 of 2011-12)- Direct Taxes - Business of Civil Construction for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-4965/15/11)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India, Union Government (No.PA 14 of 2011-12) -Railways – Performance Audit for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-4966/15/11)

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India, Union Government (No.15 of 2011-12) –Indirect Taxes- Service Tax and Customs – Performance Audit -Service Tax on Banking and other Financial Services and Duty Drawback Scheme for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-4967/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Buildings Construction Corporation Limited and the Ministry of Urban Development for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT-4968/15/11)

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) regarding allotments made under 5% Discretionary Quota in accordance with the guidelines issued *vide* Directorate of Estates O.M. No. 12035/2/97-POL.II(Pt.II) dated 17.11.1997 for the year ending 31st December, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-4969/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968:-

(i) The Central Industrial Security Force (Group "A" and "B" Civilian Gazetted Posts) Recruitment Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 438(E) in Gazette of India dated the 8th June, 2011.

(ii) The Central Industrial Security Force, Group "A" Fire Cadre Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 253(E) in Gazette of India dated the 24th March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT-4970/15/11)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007:-

(i) The Sashastra Seema Bal Combatised (General Duty) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 489(E) in Gazette of India dated the 27th June, 2011.

(ii) The Sashastra Seema Bal Head Constable, Group 'C' Combatised (Non Gazetted) Motor Transport and Mechanic Cadre posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 300(E) in Gazette of India dated the 5th April, 2011.

(iii) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal Group 'B' Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Post Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 440(E) in Gazette of India dated the 8th June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT-4971/15/11)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968:-

(i) The Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial), Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 120 in Gazette of India dated the 9th April, 2011.

(ii) The Border Security Force, Electronic Data Processing, Principal System Analyst/Deputy Inspector General and Programmer/Assistant Commandant Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 335(E) in Gazette of India dated the 21st April, 2011.

(Placed in Library, See No. LT-4972/15/11)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Act, 1992:-

(i) The Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 392(E) in Gazette of India dated the 20th May, 2011.

(ii) The Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant (Staff Officer) (Group 'A' Posts) Recruitment Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 393(E) in Gazette of India dated the 20th May, 2011.

(iii) G.S.R. 391(E) in Gazette of India dated the 20th May, 2011, containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 1019(E) dated 28th December, 2010.

(iv) The Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 411(E) in Gazette of India dated the 27th May, 2011.

(v) The Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre, (Group 'A', 'B' and 'C' Posts) Amendment Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 412(E) in Gazette of India dated the 27th May, 2011.

(vi) The Indo-Tibetan Border Police Force, Group 'A' (Gazetted) Ministerial Posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 206(E) in Gazette of India dated the 10th March, 2011.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (vi) of (4) above.

(Placed in Library, See No. LT-4973/15/11)

MADAM SPEAKER: Item No. 8, Shri Basudeb Acharia -- not present.

Shri Hukmadeo Narayan Yadav -- not present.

Item No. 9, Shri Ajay Maken.

12.02 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 3018 DATED 15.03.2011 REGARDING INNOVATIVE COURSE FOR YOUTH ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI AJAY MAKEN): I beg to lay a statement to correct the reply of Part (a) to (d) to the Lok Sabha Unstarred Question No. 3018 answered on 15.03.2011 regarding "Innovative Course for Youth" as follows:

Part of the question answered	For	Read
Part (a) to (d)	These programmes are:	Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development have developed structure of the following courses apart from the existing courses:

The reason for delay:

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-4974/15/11.

The error in the above mentioned question's reply was noticed after replying the question in the Lok Sabha. The correction could not be carried out as the Budget Session was over almost immediately.

The inconvenience caused is regretted.

12.03 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Hon. Members may send slips immediately at the Table of the House as per practice.

(i)Need to expedite approval for four laning of stretch of N.H. 17 between Poladpur and Patradevi in Maharashtra

SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG): I would draw the attention of the Minister of Road Transport and Highways on the problems faced by citizens regarding National Highway No. 17 running through the State of Maharashtra.

The NH-17 which passes through three districts of Maharasthra in Konkan region and has a length of 578 Kms is the main artery and backbone of economy of Raigad, Ratnagiri and Sindhudurga districts. Presently this road is of only two lanes. Expansion of NH-17 to four lanes has been sanctioned for the stretch between Panvel and Poladpur. The remaining part of NH-17 runs from Poladpur to Patradevi through Maharashtra. Expansion to four lanes from Poladpur to Patradevi is still under consideration.

During the year 2009-2010, 2357 accidents were reported on this NH running through Maharashtra and 517 passengers were reported dead and 1,778 were seriously injured. The stretch between Poladpur and Patradevi is notorious for its blind spots and very narrow stretches. Urgent attention is needed to maintain the National Highway in perfect order to avert accidents.

I request the Hon'ble Minister to look into the matter immediately and expedite approval for expansion of the stretch between Poladupur and Patradevi of NH-17 at the earliest.

---

* Treated as laid on the Table.

(ii)Need to provide option of learning in mother tongue/regional language to students in Kendriya Vidyalayas

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): पूरे देश में हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ना आवश्यक है तथा राज्यों में हिन्दी के साथ-साथ एक अन्य क्षेत्रीय भाषा विकल्प के रूप में छात्र की रूचि अनुसार पढ़ने का प्रावधान भी है। परन्तु केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक 3 भाषा हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत तथा क्षा 9 से 11 तक केवल 2 भाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ाने का प्रावधान है।

भारत के संविधान में उल्लिखित अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगू, बांगला, उर्दू, गुजराती, मराठी आदि के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन वैकल्पिक भाषा चयन करने का अधिकार छात्रों को नहीं देता है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के अतिरिक्त 1 अन्य क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक रूप से छात्र द्वारा लेने का विकल्प खुला रखा है, उसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भी कक्षा 1 से 8 तक जो 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उनमें से एक भाषा का विकल्प छात्र के विवेक पर चयन करने का रखा जाये क्योंकि क्षेत्रीय भाषा उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत होती है तथा छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रायः अपने घर परिवार व समाज में बातें करता है तथा पीढ़ियों से चली आ रही विरासत से अवगत होता है। यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन कक्षा 8 तक भाषा के विकल्प में क्षेत्रीय भाषा को छात्र की रूचि अनुसार चयन का अधिकार देगा तो निश्चित ही हमारी पीढ़ियों की विरासत भी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकेगी।

(iii)Need to provide houses to poor and homeless people belonging to General Category under Indira Awas Yojana

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): आवास जीवन का अभिन्न अंग है। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनका जीवन एक तरह से नारकीय बन जाता है और विकास के सारे रास्ते बंद रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार इन्दिरा आवास योजना के द्वारा गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध करवा रही है। गांव में विधवाएं हैं, विकलांग लोग और सामान्य जाति के गृहविहीन परिवार भी हैं; परन्तु इस योजना का लाभ ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिशानिर्देशों के कारण नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोगों के कभी कभार बाढ़ एवं आगजनी की घटनाओं से आवास बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें बिना घर के अपने परिवार को खेत में या सड़क पर गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है एवं सांसदों की अनुशंसा को जिला प्रशासन विचार नहीं करता है। हालांकि केन्द्र सरकार ने नियम बना रखें हैं कि सांसदों की सिफारिश पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ एवं आगजनी की घटना से सामान्य जाति के आवास के बर्बाद होने पर उन्हें इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और गांव की सामान्य जाति की गरीब विधवा एवं गरीब विकलांग को इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया जाए।

(iv) Need to provide financial assistance to the Boat Racing Associations in Kerala

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kerala boat race is a yearly event that takes place in the month of August or September in Alapuzza. Representing the unique cultural heritage and traditional legacy of Kerala, the boat race is one of the exciting socio-cultural events of the State.

The most impressive of all the boat races of Kerala is the snake Boat Race, which is commonly referred to as Chundavallams. The brilliant performance of the rowers portays the inherent sporting zeal and sportsman spirit of the local inhabitants of the southern State of India. Our former Prime Minister Late Pandit Jawaharlal Nehru was so impressed with the Snake Boat Race of Kerala that he awarded the Nehru Trophy to the winners. Till today, the winners of the Snake Boat race is awarded the coveted Nehru Trophy.

Thousands of participants participate in Boat Racing in Kerala. It also attracts tourists, domestic and foreigners, in large number. In fact, during the months of boat racing, Kerala becomes a hotspot of communal harmony, secularism and national integrity since people from all sections of the society participate in the Boat Racings.

At present, the Government of India is not extending any financial assistance or grant-in-aid for the Kerala Boat Club Racings. The Kerala Boat Club Associationn has been demanding the staus of sportspersons to the boat Racers since it is a sporting event. Every year, the Organising Committees incur huge financial losses since they are unable to meet the financial aspect of the Boat Races. The Boat Racing Associations have been demanding grant of financial assistance for a long time.

I, therefore, request the Government of India to provide financial assistance to the Boat Racing Associations in order to encourage Boat Racing in Kerala.

(v)Need to provide relief to the people affected due to flood in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद श्रावस्ती एवं बलरामपुर में अतिवृष्टि एवं राप्ती नदी की कटान से उत्पन्न विभीषिका से अस्त-व्यस्त जनमानस की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद श्रावस्ती एवं बलरामपुर के सैकड़ों गांव राप्ती नदी की तबाही से प्रभावित हैं। राप्ती नदी का स्रोत नेपाल है तथा यह नेपाल से कलकलवा की ओर लक्ष्मणपुर बैराज से भारत में आती है। जनपद श्रावस्ती के ब्लॉक जमुनहा में स्थित जगपती देवी मन्दिर एवं उसी से सटा ग्राम बारू, मरघटपुरवा में नदी का कटान तेजी से जारी है और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ब्लॉक जमुनहा का एक अन्य ग्राम वीरपुरलौकिहा के तीन मजरो में से एक मजरा राप्ती नदी में जलमग्न हो चुका है एवं दूसरे मजरे के पांच घर नदी में समाहित हो चुके हैं।

जनपद बलरामपुर के ब्लॉक बलरामपुर में ग्राम जगदही, जबदहा, सिमरहना, चौकाकला, करमहना, बेलहा, बेलवा, सुलतानजोत एवं ब्लॉक हरैया सतघरवा के बेला, बेली, गोडवा का पुरवा - साहिबानगर, गंगावख्श भागड़, चौकाखुर्द, झौहना इत्यादि ग्राम नदी के कटान से बुरी तरह प्रभावित है। इसी कटान के चलते नदी की धारा का प्रवाह कई वर्ष पहले बदल गया था जिसके चलते कोडरी घाट पुल पर किये गये करोड़ों रुपए व्यय का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों को हुए फसलों एवं पशुधन के नुकसान के कारण लगान एवं कर्ज की वसूली रोक दी जाये। खेत और घरों के कटान एवं फसल व पशुओं के नुकसान का मुआवजा दिया जाये। महामारी की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में डॉक्टरों एवं औषधियों की व्यवस्था की जाये। इसके अलावा भुखमरी से जनमानस एवं पशुधन को बचाने हेतु क्षेत्र में खाद्य सामग्री एवं पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

(vi)Need to allocate coal to thermal power units in Gujarat from Western Coal Fields

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): The State of Gujarat is on the Western Coast of India and is at a distance of more than 1600 kms from the eastern coal belt. As a result of this, the freight cost on coal is higher than the actual coal cost resulting into higher cost of generation of power. It is to be appreciated that Gujarat suffers from a negative thermal hydro mix of 92.8 against the normal ratio of 60:40 (Thermal: Hydro). Thus, the state is highly dependent on thermal generation based on coal from collieries far away from the State. This issue was taken up with the Central Government for appropriate action. In this regard, Gujarat State Electricity Corporation Ltd. (GSEC) has a total coal based generating capacity of 3,430 MW and the total coal requirement of these 4 Thermal Power Stations is 200 lakh MT per annum and against these requirement, GSEC is having coal linkages of 164.4 lakhs MT from South Eastern Coal Ltd. and only a meager of 9.3 lakhs MT from Western Coal Field. Further, GSEC is also importing 14.8 lakhs MT of Coal per annum. To fully mitigate the requirement of coal, GSEC has to import additional quantity of coal to the tune of 11 lakhs MT per annum involving additional financial burden of Rs. 440 crores per annum, which is a huge amount and if Government of India is not able to mitigate this gap, then the differential amount between imported coal and domestic coal should be borne by Government of India i.e. Rs. 440 crores per annum. Therefore, with a view to reducing the freight coast on coal, the allocation of coal from collieries of WCL would be appropriate and in the interest of the sector as a whole. This would result in reduction in transportation cost which in turn would result in enormous savings in generation cost. Government of India may kindly ensure that coal allocation to Gujarat for power generation, is made from mines nearest to the State preferably from the mines from Western Coal Fields only.

(vii)Need to prohibit the practice of carrying night soil in the country

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ड्राय लैट्रीन्स (प्रौहीबिशन) एक्ट, 1993 के अनुसार देश में ड्राय लैट्रीन्स यानी नॉन फ्लश लैट्रीन्स के निर्माण पर रोक है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके लिए एक वर्ष की जेल एवं 2000 रुपए जुर्माने की सजा है, लेकिन इसके बावजूद देश में अनेक म्युनिसिपैलिटीज द्वारा पब्लिक ड्राय टॉयलैट्स चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 2007 में योजना बनाई, इसे भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत धारा 14 (कानून के समक्ष समानता) एवं धारा 17 (अस्पृश्यता निवारण) एवं धारा 17 (शोषण विरुद्ध अधिकार) का उल्लंघन मानते हुए सजा का प्रावधान किया। कर्नाटक राज्य में सर पर मैला ढोने की प्रथा को वर्ष 1970 और सम्पूर्ण भारत में इस प्रथा को 1995 में निषेध कर दिया गया, लेकिन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले कर्नाटक राज्य में अभी भी सर पर मैला ढोकर अपना जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 8000 है। यह संख्या तो केवल एक राज्य की है। पूरे देश में न जाने अभी भी इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को जड़-मूल से समाप्त करने हेतु कानूनों के साथ-साथ सामाजिक चेतना जागृत करें और देशभर में म्युनिसिपैलिटीज द्वारा चलाई जा रही ड्राय लैट्रीन्स को समाप्त करें।

(viii)Need to provide ownership of land and caste certificates to migrated Bengali and Sindhi people living in Khajuraho Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सन् 1956, 1962 एवं 1971 में बंगाली भाई पूरे देश में विस्थापित हुए थे, जिसमें मेरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के पन्ना जिला के ग्राम कुंजवन, जरूआपुर, बाबूपुर, खसेहा, समुनाई, अहिरगुवां एवं दमचुआ में इन्हें पट्टे देकर पुनर्वास किया गया, जिसकी वर्तमान संख्या लगभग 8 से 10 हजार है।

लेकिन हमारे बंगाली भाईयों को आज 40 से 50 साल बीत जाने के उपरांत भी पट्टों के मालिकाना हक नहीं दिये गये जिससे यह अपना स्वयं का रोजगार भी प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इन बंगाली भाईयों के जाति प्रमाण पत्र भी मूल जाति के नहीं बनाए जाते हैं जिसके ये हकदार हैं, जिससे इन्हें नौकरी मिलने में भी परेशानी होती है।

साथ ही 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा में सिंध प्रांत से हमारे सिंधी भाई बहुत बड़ी संख्या में मेरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के कटनी में आकर स्थापित हुए थे, हमारे सिंधी भाईयों को 1947 से 1993 तक पट्टे दिये गये, लेकिन 1993 से सरकार ने पट्टे देना बंद कर दिया है, जिससे करीब 200 सिंधी परिवार वंचित हो गये हैं और जिन सिंधी भाईयों को पट्टे मिल चुके हैं उन्हें 50 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी पट्टों का मालिकाना हक नहीं मिल सका, जिससे इन्हें भी बंगाली भाईयों की तरह बैंक से लोन एवं अन्य स्वयं के किसी भी रोजगार करने में काफी परेशानी होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में रह रहे बंगाली एवं सिंघी भाईयों को जमीन के पट्टों का मालिकाना हक दिया जाए एवं इन्हें जाति प्रमाण दिया जाए ताकि ये लोग शिक्षा, रोजगार एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

(ix)Need to provide Scheduled Tribe certificates to all the persons belonging to the 'Gond' Tribe in Uttar Pradesh

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्ज़ापुर): भारत सरकार की मंशा समाज के निर्बल वर्गों को प्रोत्साहन एवं अपेक्षित संरक्षण देने की सुस्पष्ट अवधारणा से कम में जातियों को अधिसूचित किया गया है। स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में पूर्व में अनुसूचित जाति गोंड जो कि कालान्तर में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हुई, को कभी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं, तो कभी वर्तनी या व्यवसाय को आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करना बन्द कर दिया जाता है। 30.01.2007 के शासनादेश द्वारा 13 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में घोषित किया गया है। वर्ष 2010 तक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते रहे, परन्तु उसके बाद व्यवसाय को आधार बनाकर या वर्तनी का दोष बताकर जाति प्रमाण पत्र जारी करना बन्द कर दिया गया है। यदि किसी के माता-पिता अनुसूचित जाति/जनजाति के रहे हों तो सन्तान कैसे पिछड़ी जाति की हो सकती है। किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त क्या यह संभव है कि जीवनकाल में ही उसकी जाति बदल जाये, ऐसा संभव नहीं है।

अस्तु भारत सरकार से मांग करता हूं कि गोंड जाति के उक्त निर्बल व्यक्तियों के प्रोत्साहन एवं अपेक्षित संरक्षण हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था करे एवं किसी व्यक्ति के जारी वैधानिक जाति प्रमाण पत्र को संविधान में अधिसूचित समय तक मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

(x)Need to develop the site of Mausoleum of Madarshah in Misrikh Parliamentary Constitunecy, Uttar Pradesh as a tourist place of national importance

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, मकनपुर, जो कानपुर नगर जिलान्तर्गत आता है, में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है। यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश-विदेश से दर्शनार्थ आते हैं। यहां पर मई माह में उर्स लगता है, जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी-फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध मजार होने पर भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मदारशाह की मजार के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करके इसे विकसित करने, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने, मकनपुर को वाया कानपुर/बिल्हौर रेलवे से जोड़ने, सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ने, मकनपुर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बिल्हौर का सौन्दर्यीकरण करने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(xi)Need to provide immediate financial assistance to the patients seeking help from Prime Minister's National Relief Fund

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, बीमार व्यक्ति आज समय से लाभ नहीं उठा पा रहा है। ज्ञातव्य रहे कि इस कोष से अन्य कामों के साथ मरीजों के इलाज हेतु आर्थिक अनुदान दिया जाता है, परन्तु मरीजों के अनुदान में एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था से हजारों-लाखों मरीजों को कोष से आर्थिक अनुदान मिलने में बाधा आ रही है।

वर्तमान में इस कोष के तहत सांसदों द्वारा मरीजों के इलाज हेतु की गई संस्तुतियों की लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी के बाद आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है, यह व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक है, क्योंकि जिस गंभीर बीमार व्यक्ति को आज इलाज की आवश्यकता है, उसे यदि 6 माह या 1 वर्ष बाद स्वीकृत धनराशि मिलेगी तो वह शायद ही जिंदा रह सकेगा। हजारों रोगियों को इस व्यवस्था से समय पर इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है।

मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए सांसदों द्वारा लिखे गए पत्रों पर अविलम्ब इलाज के पात्र व्यक्तियों के लिए इलाज हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

(xii)Need to extend agricultural loan to farmers and provide adequate quantity of subsidized fertilizers to them in Tamil Nadu.

SHRI D. VENUGOPAL (TIRUVANNAMALAI): In Tamil Nadu, like several other parts of India, cultivation activities have started. This is the time when the farmers require loan to meet the expenses on purchase of agricultural inputs and to spend on agricultural activities like ploughing, planting and weeding. Complaints have come from many farmers about the lackadaisical attitude of both the Cooperative Banks and the Nationalized Banks to extend loans for these operative expenses. As far as cooperative bodies are concerned, they are guided by the national policy and in Tamil Nadu, they have been operating effectively. Hence, the Cooperative Banks in Tamil Nadu must not desist from extending loans to farmers for the basic need to commence cultivation on time. Procurement Centres are also facing closure in many of places and Regulated Market Centres are also not functioning effectively. This has led farmers to face the problem of non-availability of funds required. The exorbitant rise in fertilizer prices in the international market has created an uncertainty in India where our Government comes forward to hold talks with private fertilizer factories and extend subsidy to help farmers. Private sector fertilizer companies are not coming forward to evolve a consensus on fixing affordable price for farmers. This has given rise to short supply and scarcity.

Hence, I urge upon the Union Government to ensure that farmers get agricultural loan in time and fertilizers are made available to them at the time of their need. It has also been forecast that this year's monsoon will be less and hence it calls for immediate measures on the part of the Union Government to issue appropriate guidelines to the States and to ensure that the efforts of our farmers comes out with a rich yield.

(xiii) Need to construct a Road Over Bridge at Nadakkavu in Palakkad, Kerala

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of this House and also the Government to a long pending demand for a Railway override at Nadakkavu is Palakkad. The railway gate at Nadakkavu which is close to the Palakkad Railway Junction causes innumerable difficulties to people of this area. This gate is situated at Palakkad-Malampuzha road. Malampuzha is one of the important tourist destinations in Kerala. Hence heavy traffic will always be there in this road. Because of heavy traffic the situation becomes too worse whenever the gate is closed for the passage of trains. Since the gate is close to Palakkad junction several trains passes through this gate. The closure of gate may extend upto one hour. There have been instances of many patients got stuck in the traffic on the closed gate and lost their lives on their way to hospitals. In view of the seriousness of the situation, I urge upon the Government to take immediate steps to construct a ROB to replace this most inconvenient railway gate which is too close to Palakkad Junction.

(xiv)Need to create a new railway division under East Coast Railway Zone in Odisha

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): The East-Coast Railway zone of Odisha is the smallest zone consisting of only three railway divisions. These are Khurda Road, Sambalpur and Waltair. It is a matter of concern that several mineral-rich areas, important cities and industrial centres of Odisha remain outside the jurisdiction of East-Coast Railways. For example, steel city of Rourkela, the industrial belt of Jharsuguda, Brajaraj Nagar, the mineral-rich areas of Bondhamunda and Baleswar all are under the South-Eastern Railway Zone. In addition to these, the proposed Dhamra-Bhadrakh, Rupsa-Baripada, Baripada-Bangriposi etc. are also under the purview of South-Eastern Railway. Though small in size, the East-Coast Railway last year had contributed around 8.5% of the total railway income during last year. Hence, a new division must be created under the East-Coast Railway Zone to cater to the needs of the area. This new division should be christened as Jajpur-Keonjhar Road Railway Division and should cover the areas from Cuttack to Lakshmannath Railway station including Paradeep-Haridaspur, Daitari-Banspani, Angul-Sukinda, Talchar-Bimlagarh, Jakhpura-Daitari and Dhamra-Bhadrakh ongoing railway projects. The Jajpur Road-Keonjhar area has emerged as one of the mega steel hubs of the Asian subcontinent. Hence paramount importance must be given to this demand and Central Government should take immediate step to create on a new Division under the East Coast Railway Zone bringing all the important area/rail/link of Odisha.

(xv) Need to reopen the Andhra Cement Company in Guntur District in Andhra Pradesh

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): I would like to draw the kind attention of the august House towards the dire need to re-open the Andhra Cement Company, Durgapuram, Dachepally Mandal, Guntur District in my Narasaraopet Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh.

The Andhra Cements Limited was 75 year old unit manufacturing cement, with around 2000 employees at various levels. Due to the unknown reasons the factory was closed in July 2010. With the shutdown of the said unit, the employees are facing lot of problems causing huge losses to the Government of India and the State Government of Andhra Pradesh in terms of Central Excise Tax, Income Tax, Income tax, Vat, Royalty etc.

The said unit is well established in a industrial backward area providing employment to the people of the vicinity. Making it operational will solve a lot of problems of the families of those who are dependent on the unit.

Hence, I request the Hon'ble Minister for Commerce and Industry to take necessary steps for the revival of the unit at the earliest.

… (*Interruptions*)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदया, मुझे दो मिनट बोलने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपको बाद में समय देंगे।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : महोदया, मुझे दो मिनट समय दीजिए।

महोदया, उत्तर प्रदेश में खाद नहीं है, किसान परेशान हैं, बाढ़ से जमीन बुरी तरह से डूब गयी हैं और किसानों को खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैंने पिछली बार भी इस बात को उठाया था। जल निकासी न होने की वजह से स्थिति बहुत गंभीर हो गयी है। बाढ़ की बड़ी भयावह स्थिति हो गयी है। जनपद चन्दौली के रायलताल और धूसनोनार ड्रेन की जल-निकासी न होने से किसानों की खेती बर्बाद हो गयी है।...(व्यवधान) आज पूरे पूर्वांचल में खाद की भारी किल्लत है। ...(व्यवधान) जहां भी किसान बाढ़ से बचे हैं...(व्यवधान) पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं और सरकार यह कहती है कि मैं खाद भेजती हूं, लेकिन वह खाद जाती कहां है। सरकारी लोगों ने उस खाद को बेच डाला है और किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश, खास तौर से पूर्वांचल के किसानों के सामने खाद का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ...(व्यवधान) खाद का संकट उत्पन्न हो गया है। उसके साथ-साथ जो बाढ़ आई है, बाढ़ की विभीषिका से भी किसान बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल ...(व्यवधान) इसके लिए प्रबंध करे । ...(व्यवधान) सरकार लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने का प्रबंध करे और किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध कराए।

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

श्री रामकिशुन : महोदया, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है।

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): Shrimati Sushma Swaraj was on her legs. … (*Interruptions*) She is not being allowed to speak now. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: There is something that I want to say.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, मगर आप जरा मेरी बात को मान लीजिए। मैंने सुबह कहा था प्रश्नकाल में कि करप्शन पर 193 में डिसकशन कराएंगे, मगर हाउस से मेरी रिक्वेस्ट है।

MADAM SPEAKER: As per the List of Business, there is a discussion related to Tamils in Sri Lanka. My request to the House is that we may allow Shri T.R. Baalu a minute for making his point. Then, I will come back and we can have a full discussion on this other issue. I will allow only him because he was on his legs. Let us give him just one minute because he was on his legs.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: He has already started his speech. इसके बाद हम फुल डिसकशन करा देंगे।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Baalu, will you finish your speech quickly? Please quickly finish your speech.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, when I initiated the debate concerning the genocide and the plight of Sri Lankan Tamils, I could not continue my speech because of interruptions by the Opposition Members. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Can you do it later on?

SHRI T.R. BAALU : Madam, I am not yielding. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: उन्हें अपनी बात कहने दें।

SHRI T.R. BAALU : Madam, this House was adjourned on that day because of interruptions by the Opposition Members. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: जल्दी से खत्म कर दीजिए, क्योंकि यह भी बड़ा सेंसेटिव मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हो जाएगा, अभी कराएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी कराने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उनकी भी रिक्वैस्ट है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हम करा देंगे अनंत कुमार हेगड़े जी।

...(व्यवधान)

12.07 hrs.

At this stage Shri Ananth Kumar Hegde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाएं, 15 मिनट में यह खत्म हो जाएगा।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Can you do it later, Mr. Baalu?

SHRI T.R. BAALU : No, I will speak now only. … (*Interruptions*)

12.07 ½ hrs

At this stage, Shri T.K.S. Elangovan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam, I am not yielding. I have to speak only today. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाएं, हम देखेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : I am not yielding. I have already started my speech. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग अपनी जगहों पर जाएं, हम देखेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : I have already started my speech on the other day. As per the rules, I have to continue it today. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back because I am going to read something.

12.08 hrs

At this stage, Shri T.K.S. Elangovan and some other hon. Members went back to their seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

12.08 ½ hrs.

At this stage Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members went back to their seats

...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): What is this? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have not allowed it. Why are you so agitated? I told you I am not allowing it.

… (*Interruptions*)

12.09 hrs.

At this stage Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाएंगे, तब ही तो कराएंगे।

...(व्यवधान)

12.10 hrs.

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Notices Under Rule 193 for discussion on issue of corruption

MADAM SPEAKER: Hon. Members, there is a demand to hold a discussion on the issue of corruption. I may inform the House that 16 hon. Members have tabled notices under Rule 193 for discussion on the issue of corruption. The six notices from Sarvashri Gurudas Dasgupta, Anant Kumar Hegde, Rajiv Ranjan Singh, Dinesh Chandra Yadav, Dr. Murli Manohar Joshi and Smt. Sumitra Mahajan were received first in point of time on 15 July, 2011 at 1000 hours. These notices have been balloted and the notice tabled by Shri Anant Kumar Hegde has received first priority in the ballot.

Shri Hegde has since requested me to permit Dr. Murli Manohar Joshi to raise the discussion on his behalf. I have permitted Dr. Joshi to raise the discussion.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, our issue is a sensitive matter. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will take this afterwards. How long will it take?

… (*Interruptions*)

12.11 hrs

At this stage, Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members went back to their seats.

… (*Interruptions*)

12.12 hrs

At this stage, Shri Adhi Sankar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I wanted to take it up now. But you see what a ruckus has been created! Please, go back. I will take it up later.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I know it is very important. It is a very sensitive matter, and I myself wanted this to be taken up.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Kindly do not allow the discussion on corruption now. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.p.m.

12.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

———

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नः - 8, श्री हुक्मदेव नारायण यादव।

COMMITTEE ON AGRICULTURE
21st Report

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): मैं " खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचात्मक सुविधाएं-एक मूल्यांकन " के बारे में कृषि संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.13. Shri T.R. Baalu to speak.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I want a clarification. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him speak.

… (*Interruptions*)

14.01 hrs.

At this stage Shri Dilip Kumar Mansukhlal Gandhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : Sir, you have called me to speak. How can they disturb me?

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदया ने सुबह माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी थी, आप कृपया इन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

14.02 hrs.

At this stage Shri P. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow on 24th August, 2011 at 11.00 a.m.

14.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock On Wednesday, August 24, 2011/Bhadra 2, 1933 (Saka).

---

[*] Not recorded.